

बात तो यह है कि लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले मुख्य धारा के मीडिया (प्रचार तंत्र) ने भी जनता का साथ छोड़ दिया है। वह भी सच्चाई को जनता के सामने नहीं ला रहा है।

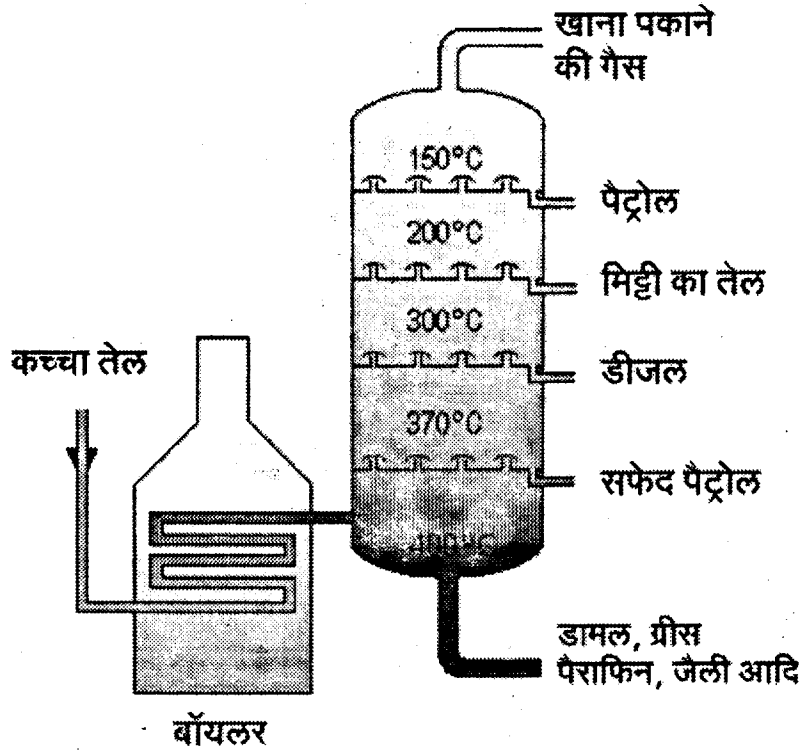
क्या है सच्चाई? सच्चाई यह है कि, हमारे देश में 70% कच्चा तेल बाहर से आयात किया जाता है जबकि हमारी खपत का 30% कच्चा तेल बाम्बे हाई आदि स्थानों से हमारे देश में ही पैदा होता है। एक बेरल (1 पीपा) अर्थात् लगभग 160 लीटर कच्चा तेल पहिले 110 अमरीकी डालर में आयात किया जा रहा था जो अब दाम घटकर लगभग 97 अमरीकी डालर में आयात हो रहा है। फिर कच्चा तेल रिफायनरी में साफ किया जाता

है। सफाई प्रक्रिया में ही कच्चे तेल से सफेद पेट्रोल, (हवाई जहाज चलाने वाला) तथा पेट्रोल की अन्य श्रेणियां, डीजल, मिट्टी का तेल आदि तैयार होता है। इस बात को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कच्चे तेल से अन्य उत्पाद उसी तरह पैदा होते हैं जैसे गेहूँ चक्की में डालने से आटा, मैदा, रवा आदि पैदा होते हैं।

शायद एक लीटर, कच्चा तेल साफ करने में रिफायनरी का कुल व्यय रु. 1/- होता होगा तथा रु. 1/- कच्चे तेल का भाड़ा व्यय प्रति लीटर से अधिक

नहीं हो सकता। रिपोर्ट यह भी बताती है कि, हमारे देश में कच्चा तेल साफ करने का व्यय दूसरे अनेक देशों की तुलना में बहुत कम बैठता है।

इस प्रकार यदि सभी खर्चों को जोड़ लिया जावे तो भी एक लीटर पेट्रोल की कीमत रु. 35/- से अधिक नहीं हो सकती। इसी प्रकार डीजल



की कीमत भी रु. 25/- प्रति लीटर से अधिक नहीं बैठेगी जबकि मिट्टी का तेल तो नीचे बैठ जाने वाले कचरे के समान है जिसकी कीमत रु. 10/- प्रति लीटर से अधिक नहीं बैठेगी। जहां तक खाना पकाने की गैस का

सवाल है तो, यह तो लाखों-करोड़ों सिलेण्डर गैस हवा में ही उड़ जाती है। इस प्रकार गैस को स्टोर करने तथा ट्रान्सपोर्ट करने का व्यय ही खाना पकाने की गैस का मुख्य व्यय है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता के घर तक पहुंचने के बाद 14 किलो की गैस के एक सिलेण्डर का व्यय रु. 50/- से अधिक नहीं हो सकता।

फिर भी सरकार कहती है कि, एक लाख करोड़ से अधिक का अनुदान (सब्सिडी) देने के बाद भी तेल कम्पनियों को एक लाख करोड़ से अधिक राशि का